रेलें	वर्ष	मामलों की सं०	बुक किए गए परेषण (चुराई गई संपत्ति का मूल्य रु० में)	मामलों की संख्या	रेल सामग्री (चुराई गई संपत्ति का मूल्य रु० में)
पश्चिम	1992-93	997	47,37,093	2428	22,60,460
	1993-94	730	60,94,282	2242	38,29,654
	1994-95	670	32,72,454	1885	31,42,687
जोड़	1992-93	16555	6,81,02,102	87504	5,25,43,012
	1993-94	12802	5,95,98,503	77906	4,63,71,990
	1994-95	10053	6,94,45,295	66764	4,62,32,140

डा० सतीश चन्द्र समिति की सिफारिशें

423. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा० सतीश चन्द्र की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो कब और इसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को सरकार द्वारा अब तक स्वीकार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) डा० सतीश चन्द्र समिति, जिसने संघ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में लागू करने तथा इन परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को समाप्त करने की मांगों की जांच की, ने 1990 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। सरकार अभी भी इस समिति की सिफारिशों की जांच कर रही है। चूंकि मुद्दे महत्वपूर्ण हैं तथा इनसे भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएं हुई हैं इसलिए सरकार आम सहमति बनाने का प्रयास कर रही है।

Joint Ventures in Operation in the Country

624. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the details of joint ventures now under operation in the country;

(b) what are their production targets;

(c) whether any other joint ventures have been approved for operation during the current year and next year; and

(d) if so, the particulars of the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) to (d) Details of the joint ventures under operation in the country and their production (data) are not centrally maintained.

During the current year upto September 1995, Government have accorded approvals 975 number of proposals for Joint Ventures involving foreign direct investment of Rs. 11513.8 Crores.

Details of the individual proposals